



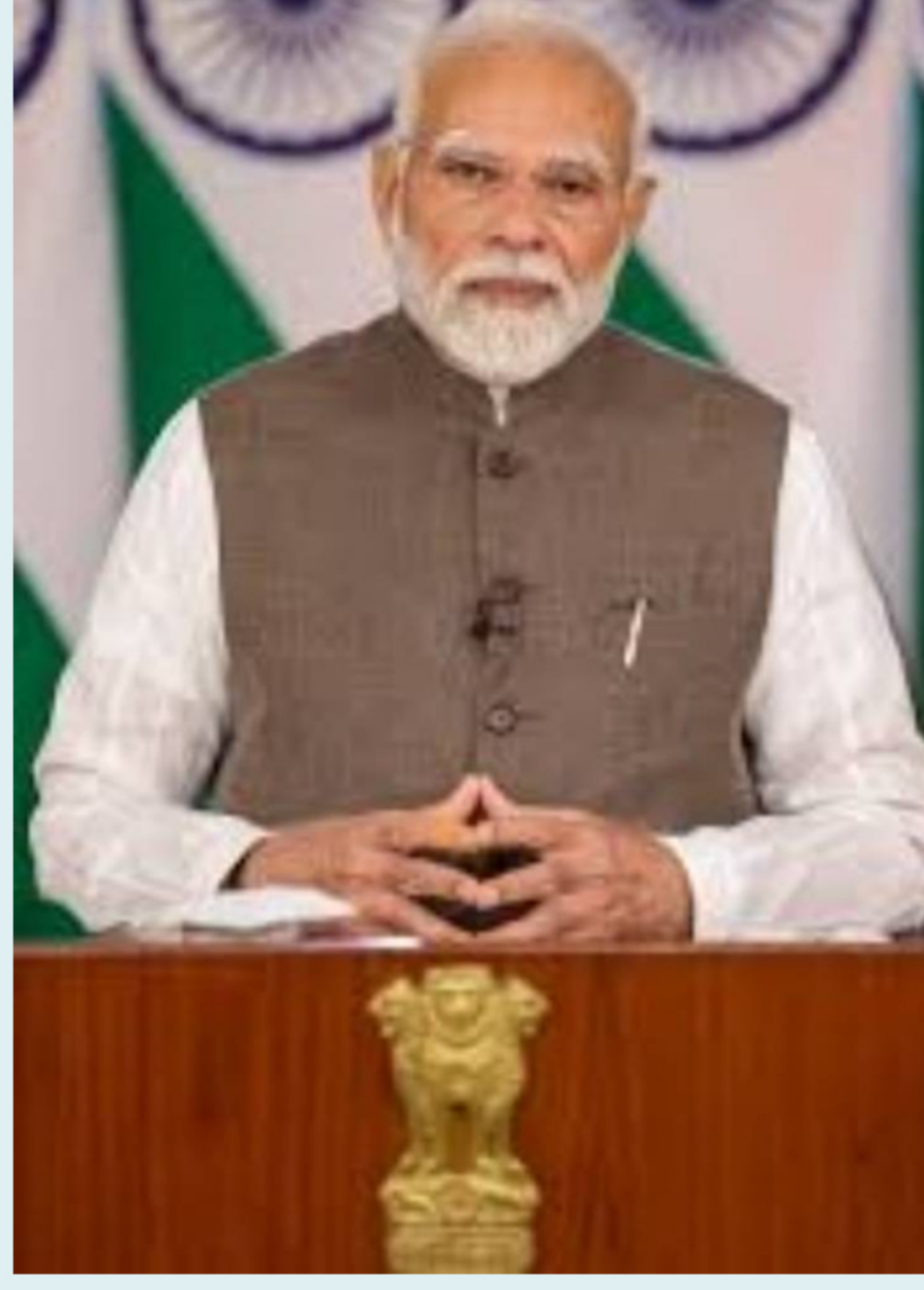


प्रेम देऊनी जगाला जवळ केले सर्वाना उरली साथ आम्हाला आवरण येते क्षणाक्षणाला कल्पनेतही नव्हते तुमचे जाणे अंधेरे राहिले जीवन गाणे आता फक्त एकच उरले तुमच्या स्मृतींना श्रद्धांजली वाहणे ॥

कै.पंजाबराव पाटील जवळगांवकर

यांच्या पुण्यतिथी निमित्त
विनम्र अभिवादन कार्यक्रम
दिनांक : 20/12/2025 रोज शनिवार वेळ : सकाळी 09.30 मि.
स्थळ : जवळगांव ता.हिमायतनगर जि.नांदेड

॥ प्रमुख उपस्थिती ॥
श्री.माधवराव पाटील जवळगांवकर
(मा.आमदार हदगांव-हिमायतनगर)
॥ विनीत ॥
समस्त गावकरी मंडळी, जवळगांव ता.हिमायतनगर



संसद ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी वाले 'SHANTI' बिल को मंजूरी दी, पीएम मोदी बोले यह ऐतिहासिक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है कि संसद के दोनों सदनों से शांति (SHANTI) विधेयक का पारित होना देश की तकनीकी व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने विधेयक के समर्थन में मतदान करने वाले सभी सांसदों का आभार जताया। पीएम मोदी ने संसद से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात कही। पीएम मोदी बिल पर क्या बोले?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कानून सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के साथ-साथ हरित विनिर्माण (ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करेगा और देश व दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की दिशा में बड़ा प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि शांति विधेयक से निजी क्षेत्र और युवाओं के लिए कई नए अवसर खुलेंगे। पीएम मोदी ने निवेशकों और नवाचार से जुड़े लोगों से अपील की कि यह भारत में निवेश करने, नवाचार करने और निर्माण करने का सबसे उपयुक्त समय है।

संसद ने गुरुवार को बिल को मंजूरी दे दी। संसद ने गुरुवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने 'भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025 को चर्चा एवं परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। उच्च सदन ने विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

शोक संदेश

नांदेड शहर के वरिष्ठ व मुअज्जज अधिवक्ता एडवोकेट एस. एम. चाऊस साहब की वालिदा का इंतिकाल हो गया है। उनके विसाल से चाऊस खानदान समेत तमाम अजीजो-अकरारिब, दोस्त अहबाब और खैरख्वाहों में गम व अंदोह की लहर दौड़ गई है।

मरहमा की नमाज़-ए-जनाज़ा लेबर कॉलोनी के मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफ्रीन जुमआ (शुक्रवार) दिनांक 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे, आसरा नगर कब्रस्तान, नांदेड में अदा की जाएगी।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह मरहमा की मगफिरत फरमाए, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नत-उल-फ़िरदीस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और पसमांदगान को सन्न-ए-जमील अता करे।
आमीना।

WORLD NEWS | पीएम मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' सम्मान, भारत-ओमान के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता

नई दिल्ली/मस्कट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया, जो ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत-ओमान के बीच गहरे कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को सशक्त करने में पीएम की भूमिका को मान्यता देता है। पीएम मोदी को मस्कट हवाई अड्डे पर 'नमस्ते' कर विदाई दी गई, जिससे दोनों देशों के पारंपरिक मित्रता और सम्मान का भाव देखा गया।

भारत और ओमान के बीच इसी दौरे के दौरान एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता

(Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नए आयाम देगा। इस समझौते के तहत ओमान भारतीय उत्पादों को लगभग 98 प्रतिशत शर्तों पर duty-free पहुंच देगा और भारत भी ओमान से आयात पर शुल्क में कटौती करेगा। समझौता ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा (AYUSH) और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा।

संयुक्त राज्य के रूसी तेल प्रतिबंध के बावजूद भारत-रूस ने डॉलर आधारित व्यवस्था की चुनौती देने की योजना बनाई: CREA रिपोर्ट

नई दिल्ली: "संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों" के बावजूद भारत और रूस ने आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना है, जिससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलने की संभावना जताई जा रही है। CREA (सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एअर) की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर की तुलना में भारत ने नवंबर 2025 में रूसी तेल की खरीद में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में भारत चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि निजी तेल कंपनियों ने आयात घटाया है, भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कूड़ तेल खरीद जारी रख है।

भारत-रूस रणनीति का लक्ष्य सिर्फ आयात बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देकर डॉलर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कम निर्भर बनाना भी है। अगले साल भारत में होने वाली BRICS बैठक में इसी विषय पर व्यापक चर्चा और संभावित घोषणाएं होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम अमेरिकी दबाव के बीच भारत-रूस ऊर्जा और आर्थिक रिश्तों को और सुदृढ़ कर सकता है।

शुक्र मना...उत्तर प्रदेश में है, बिहार हिजाब विवाद पर कमेंट को लेकर मंत्री संजय निषाद पर भड़के इम्तियाज जलील

मुंबई | बिहार से शुरू हुए हिजाब विवाद का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। असुददीन ओवैसी की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने अब यूपी के मंत्री संजय निषाद को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। यवतमाल में AIMIM की संभा को संबोधित करते हुए जलील ने संजय निषाद के लिए कहा कि शुक्र मनाओ कि यूपी में हो..अगर यहां होते तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। जलील ने गुस्से में अपशब्द का प्रयोग भी किया। जलील ने यहां हमला बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचने की घटना का जिक्र करते हुए बोला।

कोई बचाने नहीं आया... जलील ने कहा कि इस घटना से दिखता है कि हम मुश्किल दौर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी मंत्री को धमकी नहीं दी है लेकिन ऐसी घटना का विरोध जरूरी है। जलील ने आगे कहा कि कोई कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार बचाने नहीं आएंगे। जलील ने आगे कहा कि बीजेपी को तो आपको इस देश का माननी नहीं है। अगर कोई विरोध कर सकता है। कोई इनकी आंख में आंख डाल दे सकता है। तो सिर्फ ऐसा असुददीन ओवैसी कर सकते हैं। गौरतलब हो कि 15 दिसंबर की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार को धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

कि अगर हिम्मत है तो ऐसा बयान महाराष्ट्र में आकर दे। फिर हम बता देंगे। गौरतलब हो कि बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कहीं और छू देते तो क्या होता? हालांकि उन्होंने इस कमेंट के लिए बाद में सफाई दी थी।

माणिकराव कोकाटे की गिरफ्तारी की संभावना: नाशिक पुलिस टीम लीलावती अस्पताल पहुंची, डॉक्टरों से सलाह ले रही है

मुंबई: महाराष्ट्र के राजनेता और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ जारी गिरफ्तारी प्रक्रिया आज रात तेज़ गति पकड़ सकती है। नासिक जिला न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के मद्देनजर पुलिस की एक टीम मुंबई के लीलावती अस्पताल तक पहुंची है, जहाँ कोकाटे फिलहाल उपचाराधीन हैं। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से स्थिति को लेकर विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सुरक्षित रूप से की जा सके।

कोकाटे, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर कई दशक पुराने एक फ्लैट गलत तरीके से हासिल करने के आरोपों का मामला है। नासिक न्यायालय ने इस 30 वर्ष पुराने EWS / सरकारी आवास कोटा थोखाथड़ी मामले में दो वर्ष की सज़ा एवं जुर्माना सहित उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसे पुलिस द्वारा लागू किया जाना है।

यहाँ पुलिस की प्राथमिक कोशिश है कि कोकाटे के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर चिकित्सकों की सलाह लेकर ही आगे के कानूनी कदम उठाए जाएँ। इससे पहले, कोकाटे को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ वे दुपहिंए सिलाने के लिए उपचार ले रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया को तेज़ करने के प्रयास में नासिक पुलिस ने मुंबई पहुँचकर यही रणनीति अपनाई है कि गिरफ्तारी से पहले उनकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति का जायजा लिया जाए।

अधिकारी मान रहे हैं कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार ताज़ा चिकित्सीय सलाह के बाद ही गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाना आवश्यक है। यह मामला पिछले दिनों और राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे ने मंत्रिपद से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जवाबदेही का मसला अब राजनैतिक तथा कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों तथा स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की अगली कार्रवाई पर जनता और मीडिया की निगाह बनी हुई है।



लोकसभा शीतकालीन अधिवेशन (17 दिसंबर 2025): महिला आरक्षण के क्रियान्वयन पर बहस—समान प्रतिनिधित्व की निर्णायक घड़ी

संपादकीय... |

लोकसभा के शीतकालीन अधिवेशन में 17 दिसंबर 2025 को जिस मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा हुई, वह था महिला आरक्षण के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रश्न। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष—दोनों ने इस विषय को लोकतंत्र की गुणवत्ता, प्रतिनिधित्व की समानता और सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए व्यापक बहस की। चर्चा का केंद्र यह रहा कि संवैधानिक प्रावधानों के बाद अब जमीनी अमल की समय-सीमा, परिसीमन की प्रक्रिया और संक्रमणकालीन व्यवस्था कैसे तय की जाए।

महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से सहमति भी रही है और आशंकाएं भी। 17 दिसंबर की बहस में समर्थकों ने तर्क दिया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति-निर्माण अधिक समावेशी होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर महिलाओं की दृष्टि नीतियों को मानवीय और व्यावहारिक बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वहां शासन की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार देखा गया है।

वहीं विपक्ष ने समर्थन के साथ व्यावहारिक चुनौतियों पर जोर दिया। परिसीमन के बिना आरक्षण लागू होने पर क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण की मांग, और संक्रमणकाल में राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर—ये प्रमुख बिंदु रहे। कुछ सदस्यों ने आशंका जताई कि यदि समय-सीमा स्पष्ट नहीं हुई तो यह सुधार केवल कागज़ी रह जाएगा। इसलिए बहस में स्पष्ट रोडमैप और पारदर्शी नियमावली की मांग बार-बार उठी।

सरकार की ओर से यह रेखांकित किया गया कि संवैधानिक भावना के अनुरूप कानूनी और प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। परिसीमन, जनगणना-आधारित आंकड़े और निर्वाचन प्रबंधन—इन सभी चरणों को समन्वित ढंग से पूरा करने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया कि क्रियान्वयन में किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी हितधारकों से संवाद जारी रहेगा।

इस बहस का एक महत्वपूर्ण आयाम था—राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। सदन में यह सवाल उठा कि क्या दल टिकट वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, क्या संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे, और क्या आंतरिक कोटा जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। केवल संवैधानिक आरक्षण पर्याप्त नहीं; राजनीतिक संस्कृति में बदलाव भी उतना ही जरूरी है—यह संदेश चर्चा से उभरकर आया।

संपादकीय दृष्टि से देखें तो 17 दिसंबर की बहस ने यह स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण अब सिद्धांत से क्रियान्वयन के चरण में है। यहां सफलता का पैमाना समयबद्धता, निष्पक्षता और समावेशन होगा। यदि परिसीमन और उप-आरक्षण जैसे मुद्दों पर व्यापक सहमति बनती है, तो यह सुधार भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाई दे सकता है। लेकिन देरी, अस्पष्टता या राजनीतिक टालमटोल से जन-विश्वास को ठेस पहुंचेगी।

अंततः, महिला आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक न्याय का विस्तार है। लोकसभा की 17 दिसंबर 2025 की बहस ने अवसर प्रदान किया है कि सरकार और विपक्ष मिलकर स्पष्ट समय-सीमा तय करें, आशंकाओं का समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि संसद में महिलाओं की आवाज़ केवल संख्या नहीं, बल्कि नीति और नेतृत्व में निर्णायक भूमिका बने। यही इस अधिवेशन की सबसे बड़ी कसौटी और उपलब्धि होगी।

Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, भारत की आलोचना

इस्लामाबाद | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने के मामले में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस मामले में लंबा-चौड़ा बयान जारी किया है। इस बयान में न सिर्फ नीतीश कुमार का जिक्र कर घटना की कड़ी निंदा की गई है, बल्कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद के बयान की भी आलोचना की गई है। निषाद ने नीतीश कुमार के समर्थन में विवादित बयान दिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंब्राबी ने गुरुवार को यह बात कही। भारतीय राज्य बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक मुस्लिम महिला के साथ दुर्व्यवहार की हालिया घटना के बारे में बात करते हुए,



अंब्राबी ने कहा कि एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब जबरदस्ती हटाना और उसके बाद इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना बहुत परेशान करने वाला है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के एक मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से घटना का मजाक उड़ाने की भी निंदा की।

पाकिस्तान ने भारत से क्या अपील की अंब्राबी ने कहा, "यह कार्रवाई भारत में मुस्लिम महिलाओं के अपमान को सामान्य बनाने का जोखिम पैदा करती है। यह आचरण भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से इसके मुस्लिम नागरिकों के प्रति सार्वजनिक अनादर भी दिखाता है।

Top News

भारत में इस्लामिक खिलाफत को लाने की अधूरी कहानी,

भारत में इस्लामिक खिलाफत को लाने की अधूरी कहानी, तुर्की के आखिरी खलीफा और भारतीय अरबपति प्रिंस का प्लान कैसे हुआ नाकाम, जानें

इस्तांबुल: दो विश्व युद्धों के बीच 20वीं सदी का पूर्वाद्धि इस्लामिक दुनिया के लिए बेहद उथल-पुथल भरा रहा। पहले विश्वयुद्ध में जर्मनों के साथ लड़ने वाले ऑटोमन साम्राज्य की हार ने मुस्लिम दुनिया को बदलकर रख दिया। यूरोपीय शक्तियों ने पूरे मध्य पूर्व के इलाकों को बांट लिया। इसके साथ ही आधुनिक तुर्की राज्य का उदय हुआ। इसने 1300 साल से चली आ रही इस्लामिक खिलाफत को खत्म कर दिया, जिसमें खलीफा को इस्लामिक दुनिया का शासक माना जाता था। इसके बाद कई संगठनों ने खिलाफत को लाने की कोशिश की लेकिन कोई वापस नहीं ला पाया। दिलचस्प बात है कि खिलाफत को वापस लाने की सबसे पहली कोशिश आखिरी ऑटोमन खलीफा ने ही की थी। खिलाफत को फिर शुरू करने के लिए जिस जगह को चुना गया था वह भारत की एक रियासत थी, जिसके शासक को उस समय दुनिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता था।

इस्लामिक खिलाफत को बचाने की कहानी मिडिल ईस्ट आई के पत्रकार इमरान मुल्ला ने अपनी किताब 'The Indian Caliphate : Exiled Ottomans and the Billionaire Prince' में उस दौर एक अनछुए किस्से को विस्तार से बताया है। ये कहानी आखिरी खलीफा अब्दुल मसीद II और उनकी इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की आखिरी कोशिश की है। अब्दुल मसीद II मुस्लिम दुनिया के नाममात्र के नेता रहे और गद्दी पर बैठने के महज 15 महीने बाद मार्च 1924 में तुर्की गणराज्य के नेता मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने खिलाफत को खत्म कर दिया।

ऑटोमन साम्राज्य को आखिरी खलीफा को ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में बिठाकर रातों-रात देश निकाला दे दिया गया। लेकिन अब्दुलमसीद II ने

आसानी से हार नहीं मानी। वो अपने नाम के आगे आखिरी खलीफा नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने खिलाफत को फिर से जिंदा करने के लिए एक साहसिक योजना बनाई।

आखिरी खलीफा को भारत में दिखी उम्मीद मुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि अब्दुलमसीद II का विचार था कि ऑटोमन घराने की इज्जत का इस्तेमाल करके दुनियाभर के मुस्लिम नेताओं और विद्वानों के बड़े ग्रुप से खलीफा के तौर पर पहचान ली जाए। यह बिना ऑटोमन साम्राज्य के एक ऐसी संस्था होती जिसे दुनियाभर के मुसलमानों के सपोर्ट से वैधता मिले। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे इलाके से समर्थन की तरफ उम्मीद दिखी, जहां उस समय दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी थी- यानी ब्रिटिश भारत। इस योजना का अहम हिस्सा एक शादी का रिश्ता था, जो अब्दुलमसीद की बेटी राजकुमारी दुरूशेहवार और हैदराबाद के सातवें निजाम उस्मान मीर अली खान के बेटे के बीच होना तय हुआ। इस शादी की मध्यस्थता भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेना शौकत अली ने की थी।

भारत में खलीफा को तैयार करने का प्लान निजाम ब्रिटिश कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद पर राज करते थे। वह उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। ऑटोमन घराने और हैदराबाद के इस मिलन के पीछे एक बड़ी योजना थी। दुरूशेहवार से होने वाले बेटे यानी अब्दुलमसीद के पोते को नया खलीफा बनने के लिए तैयार किया जाना था। खास बात यह है कि दुरूशेहवार का हाथ मिस्र और इराक के शाही खानदानों ने भी मांगा था, लेकिन दुरूशेहवार ने हैदराबाद को चुना जो उस समय इस्लामी दुनिया में भारत के महत्व को दिखाता है।



नाकाम हुई खिलाफत को बचाने की योजना

हालांकि, आखिरी खलीफा की की योजना आखिरकार नाकाम रही। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे और अगले साल ही हैदराबाद रियासत के भारत में विलय ने इस योजना के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। निजामशाही खत्म होने के बाद अब खिलाफत पर दावे को मजबूत आधार खिसक गया था। मुल्ला लिखते हैं, एक नए तुर्की राष्ट्र बनने के बीच खिलाफत के पतन के बाद अब्दुलमसीद ने जो योजनाएं बनाई थीं, वे एक नए भारतीय राष्ट्र निर्माण के बीच विफल हो गईं।



मॉस्को: रूस ने कहा कि S-500 प्रोमिथियस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस पहली रजिमेंट ने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया ने बताया कि S-500 की तैनाती का ऐलान रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने किया है।

S-500 Missile System: रूस ने S-500 मिसाइल सिस्टम को पहली बार कॉम्बैट ड्यूटी पर किया तैनात, अब यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका भी खतरे में

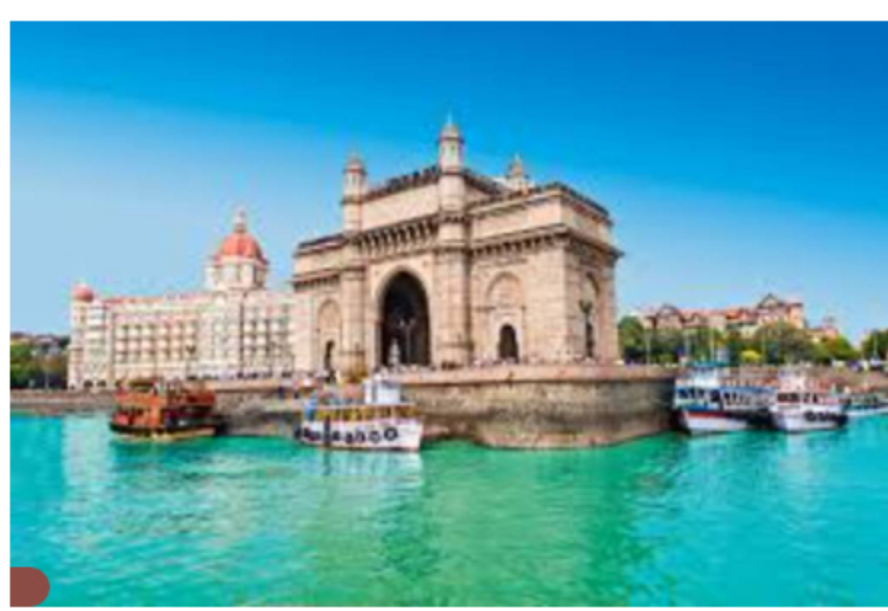
इस तैनाती से रूस की स्ट्रेटजिक मिसाइल डिफेंस की क्षमताओं में काफी वृद्धि होने की संभावना है। S-500 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक है। रूस ने इसे भारत को भी बेचने का ऑफर दिया है। हालांकि, भारत की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

रूसी रक्षा मंत्री ने क्या बताया रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव ने कहा, "अद्वितीय S-500 एयर डिफेंस मिसाइल

सिस्टम से लैस पहली रजिमेंट, जो अंतरिक्ष के करीब के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, ने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है।" उन्होंने और ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह अभी भी साफ नहीं है कि रजिमेंट को कोई कॉम्बैट अनुभव है या नहीं। रूस ने सबसे पहले दिसंबर 2024 में S-500 सिस्टम से लैस एक नई यूनिट के गठन की घोषणा की थी।

S-500 मिसाइल सिस्टम क्या है

S-500 एक लंबे समय से चल रहा रूसी प्रोजेक्ट है, जिसका विकास 2002 में शुरू हुआ था। इस सिस्टम को औपचारिक रूप से 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम उड़ान के अंतिम चरण में मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद हवाई कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस मिसाइल ले जाने वाले विमानों और कम ऑर्बिट वाले उपग्रहों को भी निशाना बनाना है।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Friday 19th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 233 , पृष्ठ 03

मराठवाड़ा से अजमेर उरुस के लिए विशेष ट्रेन चालाने का निर्णय — यात्रियों की चिंता हुई दूर

नांदेड़ | रेलवे प्रशासन ने अजमेर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध उरुस पर्व के दौरान भारी भीड़ और यात्रा की असुविधाओं को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद-अजमेर-हैदराबाद मार्ग पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ के यात्रियों को कुशल और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा।



यह विशेष ट्रेन मराठवाड़ा के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से चलकर अजमेर तक जाएगी, जिससे तीर्थयात्रियों को सीधे मार्ग से स्वाजा गरीब नवाज दरगाह के दर्शन करने का सरल विकल्प मिलेगा।

इस रेलगाड़ी को नांदेड़ मंडल के मुख्य स्टेशनों जैसे सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, बासर, मुदखेड, नांदेड़, पूर्णा, वसमत, हिंगोली, वाशिम और अकोला आदि पर स्टॉपेज प्रदान किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को भी अपने नजदीकी स्टेशन से इस

कर सकें। रेलवे अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन की सुविधाओं का लाभ लें और समय रहते अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

इस फैसले से उरुस के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रा की दिक्कतों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी और मराठी भाषी क्षेत्र के यात्री अब एक सीधी और सुविधाजनक ट्रेन सेवा के जरिए अजमेर पहुंच सकेंगे।

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिका चुनाव में महायुती गठबंधन पर बावनकुले के बयान से भाजपा उम्मीदवारों की उम्मीदें

छत्रपती संभाजीनगर में महापालिका चुनाव को लेकर भाजपा के स्थानीय नेताओं में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। वहां के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महायुती (भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना गठबंधन) के तहत ही महापालिका चुनाव लड़ने पर जोर दिया, जिससे भाजपा के कई इच्छुक उम्मीदवारों की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं।



बावनकुले ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में बैठक के दौरान कहा कि महापालिका चुनाव महायुती रूप में ही लड़ा जाना चाहिए और वाद विवाद से बचने की बात कही। इससे पहले 2015 के फार्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा करने का प्रस्ताव सामने

आया था, लेकिन शिंदे सेना द्वारा इसे 50-50 साझा करने का सुझाव दिए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में भ्रम और असंतोष बढ़ा है। आधिकारिक तौर पर 29 प्रभागों में से 18 ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां महायुती के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, जबकि अन्य

प्रभागों में मुस्लिम बहुल मतदाता होने के कारण दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनी हुई है। उम्मीदवारों के बीच दावा-प्रतिदावा और टिकट न मिलने पर बगावत का डर पैदा हो गया है, जिससे पार्टी नेतृत्व को आगे की रणनीति पर कई बैठकों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

परभणी महापालिका चुनाव: कांग्रेस का गठबंधन निर्णय कल, भाजपा-शिंदे सेना बातचीत जारी



City Name
परभणी: आगामी महापालिका चुनाव से पहले परभणी में राजनीतिक दलों की तैयारियों और रणनीतियों को गति मिल गई है। कांग्रेस ने महापालिका चुनाव में गठबंधन (आघाड़ी) तय करने के लिए 19 दिसंबर को परभणी में अपनी पार्लमेंटरी बोर्ड की बैठक बुलाकर अंतिम निर्णय लेने का ऐलान किया है। स्थानीय नेताओं और जिला नेतृत्व का कहना है कि पार्टी ने पहले “स्वबळ” (अकेले) लड़ने का नारा दिया था, लेकिन गठबंधन के अवसरों पर विचार करने का अधिकार आज मुंबई के वरिष्ठ नेतृत्व ने स्थानीय स्तर को सौंपा है।

परभणी: आगामी महापालिका चुनाव से

पहले परभणी में राजनीतिक दलों की तैयारियों और रणनीतियों को गति मिल गई है। कांग्रेस ने महापालिका चुनाव में गठबंधन (आघाड़ी) तय करने के लिए 19 दिसंबर को परभणी में अपनी पार्लमेंटरी बोर्ड की बैठक बुलाकर अंतिम निर्णय लेने का ऐलान किया है। स्थानीय नेताओं और जिला नेतृत्व का कहना है कि पार्टी ने पहले “स्वबळ” (अकेले) लड़ने का नारा दिया था, लेकिन गठबंधन के अवसरों पर विचार करने का अधिकार आज मुंबई के वरिष्ठ नेतृत्व ने स्थानीय स्तर को सौंपा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शरद पवार गुट ने भी अपनी स्वतंत्र तैयारी तेज कर रखी है और फिलहाल वरिष्ठ नेतृत्व से निर्देशों का इंतजार कर रही है। उद्धव सेना के कार्यकर्ता भी महापालिका के लिए गठबंधन के अनुकूल संकेत दे रहे हैं, लेकिन सभी दल संभावित गठबंधन विकल्पों और रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं।

Maharashtra Politics | भाईजान की 'पतंग' से महाराष्ट्र में क्यों डर रही शिंदे की शिवसेना?

भाईजान की 'पतंग' से महाराष्ट्र में क्यों डर रही शिंदे की शिवसेना, संजय शिरसाट की मांग पर भड़के इम्तियाज जलील

मुंबई | महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई बीएमसी चुनावों के साथ कुल 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। आयोग के शेड्यूल के अनुसार 15 जनवरी को वोटिंग के बाद अगले दिन यानी 16 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आयोग के शेड्यूल जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने AIMIM के चुनाव चुन्ह पतंग पर रोक लगाने की मांग की है। शिंदे की सेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि निकाय चुनाव और मकर संक्रांति का पर्व एक ही दिन है। ऐसे में एआईएमआईएम के 'पतंग' चुनाव चिह्न पर रोक लगाई जाए। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने इस मांग को खारिज करते हुए इसे 'हास्यास्पद' बताया। जलील ने दी शिरसाट को चुनौती महाराष्ट्र के छत्रपतिसंभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) से आने वाले शिरसाट ने कहा कि वह अपनी मांग को लेकर निर्वाचन आयोग से संपर्क करेंगे।



गौरतलब हो कि मकर संक्रांति का पर्व भारत के तमाम हिस्सों में व्यापक रूप से पतंग उत्सव के रूप में जाना जाता है। गौरतलब हो कि 2017 में असुददीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव लड़ा था। तब ओवैसी की पार्टी ने मुंबई और औरंगाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। AIMIM नेता और औरंगाबाद के

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने शिरसाट की मांग को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस व्यक्ति (शिरसाट) को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 27 नगर निकायों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

घड़ी न पहनें बीजेपी-शिवसेना नेता जलील ने कहा कि मकर संक्रांति के आसपास महानगरपालिका चुनाव होना महज एक संयोग है। उन्होंने कहा कि मैं इस साल पतंग जरूर उड़ाऊंगा, चूंकि यह एक हिंदू त्योहार है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वह (शिरसाट) भी पतंग उड़ाएं। महायुति सहयोगी NCP के चुनाव चिह्न घड़ी को लेकर इशारा करते हुए एआईएमआईएम नेता ने शिवसेना और भाजपा नेताओं से अगले महीने तक घड़ी न पहनने की अपील की है। जलील ने कहा कि मैं भी आयोग से संपर्क करूंगा। अगर कोई भी चीज मतदाताओं को प्रभावित करती है, तो निर्वाचन आयोग को उस पर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न घड़ी है जबकि उद्धव ठाकरे की सेना का चुनाव चिह्न मशाल और शिवसेना को चुनाव निशान धनुष-बाण है।



महाराष्ट्र में पूर्व विधायक प्रज्ञा सातव ने थामा कमल, चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस झटका, बीजेपी बोली-सबकी पार्टी

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और दिग्गज नेता राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुंबई कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रवींद्र चव्हाण मौजूद रहे। प्रज्ञा सातव का कांग्रेस छोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका संपर्क सीधे कांग्रेस हाईकमान से था और वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं।

राजीव सातव के कोरोना काल में निधन

के बाद प्रज्ञा सातव को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था और उनका पहला कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें फिर से विधान परिषद भेजा गया। पेशे से डॉक्टर प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को हिंगोली जिले में मजबूती मिली है। उनके साथ कई अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। बावनकुले ने उनका स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल सभी नेताओं को भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं दीं।

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को होंगे। इसी अवसर पर बीजेपी ने अपना चुनावी थीम सांग भी जारी किया है, जिसमें पार्टी को सभी की पार्टी के रूप में पेश किया गया है।

BMC Polls 2026: मनसे के चलते मुंबई में टूटी कांग्रेस-उद्धव ठाकरे की दोस्ती, MVA में एक नई पार्टी की होगी एंट्री?

मुंबई | मुंबई में आगामी बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव आया है। महा विकास आघाड़ी (MVA) के तीन मुख्य घटक—कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और एनसीपी—बीते दिनों तक साथ थे, लेकिन अब MVA में दरार स्पष्ट रूप से दिख रही है। आगामी चुनावों में कांग्रेस ने एकल (सोलो) उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, जिससे गठबंधन राजनीति में नया मोड़ आया है।

मुख्य वजह यह रही कि कांग्रेस मुंबई यूनिट ने मनसे (MNS) के साथ किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। मनसे के मराठी पहचान और 'आउटसाइडर' जैसे मुद्दों के कारण कांग्रेस को डर था कि इसका असर उसके उत्तरी भारतीय और मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ेगा, जिनका वह समर्थन पाने की कोशिश कर रही है।



इसी को लेकर कांग्रेस की स्थिति की स्पष्ट घोषणा हुई और उसने तय किया कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस ने MVA में सहयोगी शिवसेना (UBT) के साथ गठबंधन फेल होने पर अपना कदम अलग करते हुए बताया कि वह स्वतंत्र रूप से सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अलग-अलग

दलों के विचार अलग हैं और कांग्रेस अपने मंच पर चुनाव लड़ेगी।

उधर, शिवसेना (UBT) ने मनसे के साथ समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच बातचीत जारी है,

और चर्चा है कि जल्द ही यह गठबंधन और विस्तार से तय हो सकता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मुंबई में तीन-तरफा मुकाबला—कांग्रेस, शिवसेना-मनसे और बीजेपी/महायुति—का समीकरण बन सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ा जाना MVA के भविष्य को चुनौती देता है और इससे बीजेपी/महायुति को फायदा मिल सकता है। वहीं खुद मनसे की भूमिका और उसकी सीट-शेयरिंग रणनीति भी इस बार चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगी।

इस बदलाव के बाद मुंबई के नागरिक निकाय में सत्ता संरचना और राजनीतिक समीकरण भी काफी प्रभावित होंगे, क्योंकि चुनाव में तीन-तरफा टकराव के कारण पारंपरिक वोट बैंक बँट सकते हैं और नए गठबंधनों का उदय भी दिख सकता है।



नांदेड़ वॉक्स

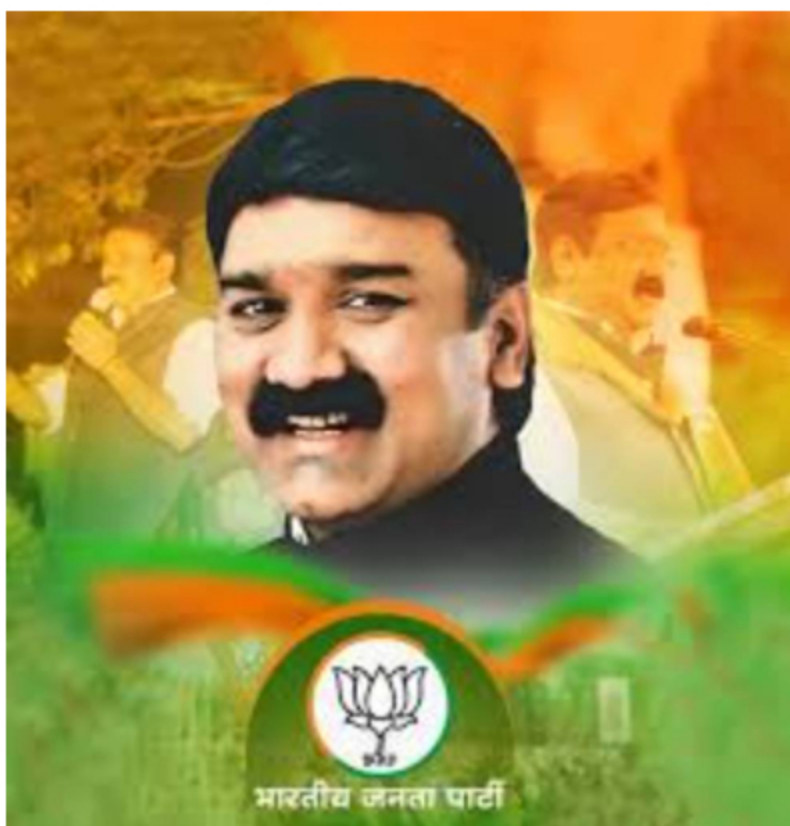
नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



नांदेड़ग्राम टाईम्स

Friday 19th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 233 , पृष्ठ 04

राज्यसभा में 'शांति विधेयक' पर डॉ.अजीत गोपछड़े का प्रखर समर्थन, कहा—यह भारत को महासत्ता बनाने की दिशा में निर्णायक कदम



नई दिल्ली : राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा से जुड़े 'शांति विधेयक' पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े ने विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल ऊर्जा नीति नहीं,

बल्कि भारत की सुरक्षा, शांति और वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध देशहित के खिलाफ है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा भारत को स्थायी, स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली देने में अहम भूमिका निभाएगी।

राज्यसभा सांसद डॉ. गोपछड़े ने भगवान गौतम बुद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत शांति और करुणा की भूमि है, और यही भावना इस विधेयक के नामकरण में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के

साथ परमाणु सहयोग भारत पर वैश्विक भरोसे का प्रमाण है। कुडनकुलम और जैतापुर जैसे संयंत्र देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देंगे।

मेडिकल क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर केयर, पेट स्कैन और रेडियो आइसोटोप के माध्यम से परमाणु ऊर्जा आम जनता की सेवा कर रही है। सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कैंसर उपचार केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 2014

के बाद परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग दोगुनी हुई है, 21 नए रिएक्टर जोड़े गए हैं और बजटीय आवंटन 9,800 करोड़ से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है। लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल की जाए।

राज्यसभा सांसद डॉ.अजीत गोपछड़े ने कहा कि यह विधेयक भारत की ऊर्जा-संपन्न ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से मजबूत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।

● ● ● ● ● ●

नांदेड़ महानगरपालिका की सत्ता किसके हाथ? महायुती में फूट से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें

नांदेड़-वाघाळा महानगरपालिका चुनावों को लेकर राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। 2017 के निष्कर्षों में कांग्रेस ने 81 में से 73 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी और नगर निगम में सत्ताधारी रही थी, लेकिन अब मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट और स्थानीय राजनीति में बदलाव से महायुती गठबंधन के सहयोगियों — भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी — के बीच राजनैतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। कांग्रेस अब सत्ता को बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, खासकर तब जब पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिससे स्थानीय वोट बैंक में विभाजन की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।



महानगरपालिका चुनावों से पहले महायुती की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। पहले महापालिका और नगर पंचायती चुनावों में सहयोगियों ने मिलकर मुकाबला किया था, लेकिन इस बार तीनों पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। नांदेड़ नगर निगम की 81 सीटों की संरचना में अभी तक कांग्रेस के पास 73 सीटें हैं, भाजपा के पास 6 और शिवसेना के पास 1 सीट है, जबकि अन्य के

पास 1 सीट है। हालांकि यह पिछली स्थिति है, और आगामी चुनाव के परिणाम इन आंकड़ों को बदल सकते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बीच नगर के मुख्य मुद्दों में सड़क अव्यवस्था, पानी की अनियमित आपूर्ति और कचरा प्रबंधन शामिल हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं और चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस अपनी सत्ता बचा पाती है या भाजपा-महायुती अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है।

सातबारा दुरुस्ती के नाम पर रिश्वत मांगने वाला मंडल अधिकारी एसीबी के रडार पर



नांदेड़ जिले के कंधार तहसील अंतर्गत सातबारा दुरुस्ती के बदले तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले मंडल अधिकारी शेख नवाज के खिलाफ कंधार पुलिस थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। कुरूला मंडल क्षेत्र के 70 वर्षीय किसान की भूमि के सातबारे में नाम दुरुस्ती के लिए प्रस्ताव तहसील कार्यालय से मंजूरी हेतु भेजा गया था। इसी कार्य के बदले मंडल अधिकारी ने किसान से तीन हजार रुपये की मांग की। किसान ने इसकी शिकायत नांदेड़ एसीबी से की। एसीबी ने जांच के बाद सापळा रचाया, लेकिन संदेह होने पर आरोपी ने पैसे स्वीकार नहीं किए और मौके से फरार हो गया। रिश्वत की मांग साबित होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

नांदेड़ में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार बेनकाब, FDA की सख्त कार्रवाई; 12 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द, 32 निलंबित



नांदेड़ शहर में मेडिकल दुकानों के माध्यम से नशीली दवाओं और गोलीयों की अवैध बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है। भी उल्लंघन किया जा रहा था। इसके चलते प्रशासन ने 47 मेडिकल दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा था।

इस प्रकरण में खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मेडिकल दुकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली गोलीयां बेचे जाने की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 12 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए हैं, जबकि 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस कार्रवाई से पूरे नांदेड़ शहर में खलबली मच गई है।

नांदेड़ शहर को एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र (एजुकेशनल हब) के रूप में जाना जाता है। यहां महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए आते हैं। ऐसे में मेडिकल दुकानों से नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता छात्रों और युवाओं

के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही थी। इस संबंध में कांग्रेस सांसद रविंद्र चव्हाण ने पूर्व में एक बैठक के दौरान पालकमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालकमंत्री ने खाद्य एवं औषध प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

इन आदेशों के बाद FDA ने नवंबर महीने में नांदेड़ शहर और जिले के विभिन्न हिस्सों में विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान यह सामने आया कि कई मेडिकल दुकानों में डॉक्टर की वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना नशीली गोलीयां बेची जा रही थीं, साथ ही औषधि कानून के अन्य नियमों का

प्राप्त

संतोषजनक न पाए जाने पर 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 12 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य मेडिकल दुकानों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित होने की जानकारी भी खाद्य एवं औषध प्रशासन ने दी है।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध रूप से नशीली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही, यह कार्रवाई उन मेडिकल दुकानदारों के लिए एक कड़ा संकेत है जो कानून की अनदेखी कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

● ● ● ● ● ●

नांदेड़ में 14 वर्षों में 42 दलित-आदिवासी हत्याएं, 1478 अत्याचार मामले दर्ज

नांदेड़ | संवाददाता:

पुरोगामी महाराष्ट्र में विकास और सामाजिक समरसता की बातें की जा रही हैं, लेकिन नांदेड़ जिले में बीते 14 वर्षों (2012-2025) में जातीय द्वेष और सामाजिक अत्याचार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम (अर्टोसिटी एक्ट) के तहत 1478 मामले दर्ज हुए, जिनमें 42 लोगों की हत्या शामिल है।

2024 में 163 मामले दर्ज हुए और 6 हत्याएं हुईं, जबकि 2023 में 149, 2021 में 144, 2020 में 134, 2022 में 128 और 2025 में अब तक 122 मामले सामने आए हैं। पिछले 14 वर्षों में हत्या और अत्याचार की घटनाओं ने 42 परिवारों से सहारा छीन लिया। समाजकल्याण विभाग

ने अब तक 1453 पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसकी कुल राशि 10 करोड़ 29 लाख 93 हजार 750 रुपये है। हत्या या गंभीर अत्याचार से हुई मृत्यु के मामलों में एक पीड़ित परिवार को 8 लाख 25 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान है।

अर्टोसिटी एक्ट के तहत दिवंगत परिवार के एक पात्र वारिस को सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान है। सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे ने कहा कि आर्थिक मदद और नौकरी के प्रस्तावों के माध्यम से पीड़ित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा रहा है।

हालांकि, लगातार बढ़ती जातीय हिंसा यह सवाल खड़ा करती है कि केवल कानून और आर्थिक सहायता ही पर्याप्त हैं या समाज में संवेदनशीलता और सख्त कार्रवाई भी जरूरी है।



दुधड में सोयाबीन खरीदी केंद्र का शुभारंभ, किसानों को होगी बड़ी राहत

हिमायतनगर /संवाददाता — हिमायतनगर तहसील के दुधड गांव में सोयाबीन खरीदी के लिए नए खरीदी केंद्र का शुभारंभ बुधवार को पूर्व विधायक माधवराव पाटील जवलागांवकर के करकमलों से हुआ। इस केंद्र के शुरू होने से दुधड और आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी।

जवलागांवकर ने खरीदी केंद्र के संचालकों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि माल की तौल, गुणवत्ता जांच और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि किसानों का भरोसा बना रहे। जवलागांवकर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी उपज बेचने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करें। संचालकों

को भी निर्देश दिए कि वे किसानों को पंजीकरण, दस्तावेज और खरीदी प्रक्रिया के संबंध में पूरा मार्गदर्शन दें। कार्यक्रम में दुधड, वालकेवाडी और सोनारी के कई किसान, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसानों ने उम्मीद जताई कि इस केंद्र से उन्हें उचित मूल्य समय पर मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

शुभारंभ अवसर पर



किनवट में राजस्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप, भाजपा विधायक की शिकायत पर मंत्री ने दिए जांच के आदेश

किनवट | संवाददाता

किनवट तालुका में तहसील कार्यालय के कामकाज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भाजपा विधायक भीमराव केराम ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मंडल अधिकारी पर आदिवासी नागरिकों के मूलभूत कार्यों की जानबूझकर अनदेखी करने तथा गौण खनिज चोरी करने वाले माफियाओं से मिलीभगत कर उन्हें संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में विधायक केराम ने नागपुर में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मंत्री ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

विधायक केराम ने बताया कि शिकायत में तहसीलदार शरदा चौडेकर, नायब तहसीलदार महमद रफीक और मंडल अधिकारी जयराम गाडे के गौण खनिज चोरी में लिप्त माफियाओं से सीधे संबंध होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने

मांग की है कि तीनों अधिकारियों की गहन विभागीय जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार शुक्रवार से सोमवार के बीच बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ देते हैं और मुख्यालय में निवास नहीं करते। साथ ही तहसीलदार व नायब तहसीलदार पर सरकारी कार्य करने वाले ठेकेदारों को परेशान कर अवैध रूप से धन की मांग करने के आरोप भी लगाए गए हैं। विधायक केराम के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की सात दिनों के भीतर जांच कर अब तक प्राप्त सभी शिकायतों की विस्तृत पड़ताल करने के निर्देश विभागीय आयुक्त के माध्यम से दिए गए हैं।

आदिवासी नागरिकों से जुड़े मामलों में भी गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। शिकायत के अनुसार आदिवासी किसानों के वारसा फेरफार के प्रकरण जानबूझकर लंबित रखे जा रहे हैं।

संबंधित नागरिक जब कार्यालय में संपर्क करने जाते हैं तो उन्हें मिलने से इनकार किया जाता है और मिलने पर भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया जाता है।

विधायक केराम ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि आदिवासियों के मूलभूत कार्यों की अनदेखी करने और गौण खनिज माफियाओं को सहयोग देने के आरोपों को देखते हुए नायब तहसीलदार और मंडल अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। वहीं तहसीलदार की भूमिका की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाए।

इस मामले में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा जांच के आदेश दिए जाने से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अब सभी की नजरें विभागीय जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई होती है।

● ● ● ● ● ●